बिहार की बिजली का आज तय होगा भविष्य

संवाददाता ■ पटना

- योजना आयोग ने बुलाया देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन
- भाग लेने को रवाना हुए ऊर्जा मंत्री व बिजली बोर्ड के अध्यक्ष

17 जुलाई को देश भर के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार की बिजली का भविष्य तय होगा. योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की ओर से बुलायी गयी इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे करेंगे. इसमें भाग लेने के लिए सोमवार को ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव व बिजली बोर्ड के अध्यक्ष प्रभात कुमार राय नयी दिल्ली के लिए रवाना हुए.

पंचवर्षीय योजना पर चर्चा होगी

बैठक के संबंध में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इसमें 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना पर चर्चा होगी. 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार ने क्या किया और 12वीं में क्या किया जायेगा, इस पर व्यापक रूप से बिहार अपना पक्ष रखेगा. इस नाते यह बैठक तय करेगी कि अगले पांच साल में बिहार की बिजली व्यवस्था कैसी होगी. कोल लिंकेज को लेकर मंत्री ने कहा कि यह संकट पूरे देश में है. 10 हजार मेगावाट की इकाई तैयार है, पर कोयला के अभाव में यह चालू नहीं हो पा रही है. जहां तक बिहार का सवाल है तो राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे होने के कारण इस राज्य को बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता है. कृषि रोड मैप के अनुसार बिजली की पूरी योजना बनायी गयी है. सबसे अधिक पानी, तीन फसलों वाली जमीन होने के बावजूद बिजली नहीं होने से फसल के पैदावार पर असर हो रहा है. ग्रामीण विद्युतीकरण की समस्या है. अब तक मात्र 10 फीसदी बीपीएल परिवार को ही बिजली की सुविधा दी जा रही है.

14 हजार करोड़ की मांग

राज्य सरकार की मांग है कि शत-प्रतिशत परिवारों को बिजली की सुविधा दी जाये. इसके लिए 14 हजार करोड़ की मांग की गयी है. इसी तरह पंचवर्षीय योजना के तहत 12 हजार करोड़ से अधिक की राशि मांगी गयी है. संचरण व्यवस्था पर मंत्री ने कहा कि बिहार की क्षमता फिलहाल चार हजार मेगावाट की है, लेकिन आनेवाले वर्षों में बिजली के लोड को देखते हुए संचरण व्यवस्था को और दुरुस्त करना होगा. इसके लिए भी राशि की आवश्यकता होगी. बिहार विभाजन के बाद डीवीसी से हिस्सेदारी व पूर्वी प्रक्षेत्र से अनावंटित कोटा भी बिहार को मिले, इस पर बिहार अपना दावा करेगा.